बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 43 ● नई दिल्ली ● शनिवार 22 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर 25 नवंबर को रहेगा अवकाश

मुरादाबाद। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के अवसर पर जनपद में 25 नवंबर 2025 को अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने इस संबंध में बताया कि कार्यकारी आदेश के अंतर्गत पूर्व में 24 नवंबर 2025 को अवकाश घोषित किया गया था परंतु 20 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश शासन (सामान्य प्रशासन) के स्तर से जारी शासनादेश के अनुसार अब 24 नवंबर के स्थान पर 25 नवंबर (मंगलवार) को जनपद में अवकाश रहेगा।

दिल्ली के स्कूलों ने प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश माना, रद्द हुई खेल समेत बाहरी गतिविधियां

नई दिल्ली ।

प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि और जनता की कड़ी निगरानी से भरे इस हफ्ते में, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, दोनों ने अपना ध्यान ज़हरीली हवा के सबसे कम उम्र के और सबसे कमज़ोर शिकार, यानी स्कूली बच्चों पर केंद्रित किया है। विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है। इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग छात्रों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक असामान्य रूप से सीधी टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सवाल उठाया था कि दिल्ली सरकार राजधानी के सबसे प्रदूषित महीनों में भी आउटडोर खेलों का आयोजन क्यों जारी रखे हुए है। उन्होंने टिप्पणी की थी कि बच्चों को नवंबर और जनवरी के बीच आउटडोर खेलों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में विफल रहे हैं, और ज़ोर देकर कहा कि इन खतरनाक महीनों में बाहरी गतिविधियों को बाहर रखने के लिए खेल कैलेंडर में संशोधन किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी बताया कि वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुँचने के बावजूद इस महीने कई आउटडोर खेल आयोजनों की योजना बनाई गई है। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि खेल कैलेंडर तैयार करने की ज़िम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, और उन्होंने एक फल्मोनोलॉजिस्ट द्वारा साझा की गई एक तस्वीर भी पेश की, जिसमें बच्चों के फेफड़ों पर

सूक्ष्म कण प्रदूषण के प्रभाव को दिखाया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या दांव पर लगा है। अगर हाईकोर्ट के शब्द तीखे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के शब्द विनाशकारी थे। एक दिन पहले ही, दिल्ली में बिगड़ते वायु संकट की समीक्षा करते हुए, शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से सभी स्कूली खेलों को स्वच्छ महीनों में स्थानांतरित करने के निर्देश तुरंत जारी करने को कहा था। पीठ ने कहा कि नवंबर और दिसंबर के दौरान बच्चों को बाहरी गतिविधियों के लिए उजागर करना स्कूली बच्चों को गैस चैंबर में डालने के समान है। यह टिप्पणी प्रदूषण की गंभीरता और सरकार की धीमी प्रतिक्रिया, दोनों को रेखांकित करती है। ये चेतावनियाँ एक महत्वपूर्ण क्षण में आई हैं। पिछले हफ़्ते, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में गिर गया, जिस स्तर पर स्वस्थ वयस्कों को भी घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर वर्षों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि बच्चे वयस्कों की तुलना में प्रदूषित हवा के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील होते हैं। उनके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे होते हैं; वे तेज़ी से साँस लेते हैं; वे ज़्यादा समय बाहर बिताते हैं; और उनका छोटा शरीर प्रति साँस ज़्यादा प्रदूषक अवशोषित करता है। अध्ययनों से पता चला है कि पीएम2.5 और पीएम10 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से न केवल फेफड़ों की क्षमता कम होती है, बल्कि श्वसन तंत्र के विकास में स्थायी रूप से बदलाव आ सकता है, अस्थमा हो सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो सकती है और संज्ञानात्मक प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। दिल्ली के कई परिवारों के लिए, यह अब एक अमूर्त स्वास्थ्य समस्या नहीं रही, बल्कि अब इनहेलर, लगातार खांसी, खेलने का समय रद्द होने और बाल चिकित्सा परामर्शों में वृद्धि का मौसम बन गया है। बाल रोग विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि हर नवंबर में अस्पताल जाने वालों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है, अक्सर 30-40 प्रतिशत तक।

जी-20 में मोदी की सुरक्षित यात्रा पर जयराम रमेश का तंज, ट्रंप के बायकॉट का किया जिक्र!

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने वार्षिक अंतर-सरकारी बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

कांग्रेस महासचिव (संचार) ने एक्स पर एक पोस्ट में यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री हाल ही में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के लिए कुआलालंपुर नहीं गए, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आमने-सामने की बातचीत से बचा जा सके। रमेश ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री आज और कल दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वह ऐसा सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे हैं। याद कीजिए कि कुछ दिन पहले श्री मोदी भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के लिए कुआलालंपुर नहीं गए थे क्योंकि वहाँ

उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से आमने-सामने होना पड़ता। यह असाधारण है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के जी-20 के एकजुटता, समानता और स्थिरता के विषयों का इस आधार पर विरोध करता है कि ये अमेरिका-विरोध के समान हैं। संयोग से, यह वही मार्को रुबियो हैं जिन्होंने 10 मई को शाम 5:37 बजे दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने की सबसे पहले घोषणा की थी। रमेश ने यह भी बताया कि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अगले ल20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेज़बानी अमेरिका 2026 में करने वाला है। उन्होंने कहा कि ल20 की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। भारत ने नवंबर 2023 में इंडोनेशिया से कार्यभार संभाला था और नवंबर 2024 में ब्राज़ील को सौंप दिया था। अब दक्षिण अफ्रीका को अमेरिका को सौंपना है, जो इस बार मौजूद नहीं होगा। इसलिए अगला ल20 शिखर सम्मेलन एक साल बाद अमेरिका में होगा। तब तक, संभवतः, भारत का अमेरिका के साथ व्यापार (या) समझौता हो चुका होगा। लेकिन अगर पिछले सात महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने 61 बार दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया है, तो सोचिए कि अगले बारह महीनों में वह कितनी बार इन दावों को दोहराएँगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, क्या मेरे अच्छे दोस्त के साथ गले मिलना फिर से शुरू होगा या सिर्फ़ हाथ मिलाना होगा या श्री मोदी नहीं जाएँगे - यह तो समय ही बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हुए। अपने प्रस्थान वक्तव्य में, प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन को एक विशेष शिखर सम्मेलन बताया। दक्षिण अफ्रीका, जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जो अफ्रीकी धरती पर आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन होगा। 2023 में भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान, अफ्रीकी संघ जी-20 का सदस्य बन जाएगा।

नवजात तस्करी रैकेट पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती, दो महिलाओं की ज़मानत रद्द

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एक बड़े अंतरराज्यीय तस्करी रैकेट में कथित रूप से शामिल दो महिलाओं की ज़मानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध बेहद गंभीर और समाज की नैतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यह बेहद गम्भीर मामला है. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अजय दिग्पाल ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि नवजात शिशुओं की तस्करी बच्चों के अधिकारों और गरिमा पर सीधा हमला है और इसे किसी भी स्थिति में सामान्य अपराध नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा यह रैकेट दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है. कई आरोपी अभी भी फरार हैं और कुछ बच्चों का अब तक पता नहीं चल पाया है. कोर्ट ने माना कि सेशन कोर्ट ने सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने के आधार पर जमानत दे दी जबकि अपराध की गंभीरता, आरोपियों की भूमिका और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया. पुलिस के अनुसार पूनम रैकेट की मुख्य संचालिका है जो नवजात बच्चों की खरीद, कमीशन तय करने और उन्हें खरीददारों तक पहुंचाने का काम संभालती थी. बिमला को तस्करी किए गए बच्चों की प्राप्ति और आगे वितरण का जिम्मा सौंपा जाता था. दोनों महिलाओं पर आरोप है कि वे पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रही हैं हाईकोर्ट ने कहा कि जांच अभी पूरी तरह सम्पन्न नहीं हुई है और कुछ आरोपी व बच्चे अब भी ट्रेस नहीं हुए हैं. ऐसे में मुख्य आरोपियों को रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है. कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि रिहाई के बाद इनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. इन सभी कारणों को देखते हुए हाईकोर्ट ने दोनों महिलाओं की ज़मानत रद्द करते हुए उन्हें सात दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया.

कर्तव्य का पद, शक्ति का नहीं: सीजेआई गवई ने 41 साल के सफर को बताया संतोषजनक, बोले- न्यायपालिका का कप्तान बनना सौभाग्य की बात

नई दिल्ली । 23 नवंबर को अपनी सेवानिवृत्ति से पहले, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपना विदाई भाषण देते हुए, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने गुरुवार को कहा कि उनके 41 साल के करियर का सबसे बड़ा सौभाग्य उस समय भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करना था जब देश भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। उन्होंने अपने अंतिम संबोधन में संवैधानिक मील के पत्थर को केंद्र में रखते हुए कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस समय भारतीय न्यायपालिका का कप्तान था जब भारत भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था। गवई ने अपने कार्यकाल के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार किया और याद दिलाया कि संविधान, जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने कहा था, एक विकासशील दस्तावेज़ है, देश की बदलती आकांक्षाओं के अनुकूल ढलता रहा है।

उन्होंने कहा कि उनके न्यायिक दर्शन को डॉ. बीआर अंबेडकर और उनके पिता ने गहराई से आकार दिया है। उन्होंने कहा, डॉ. अंबेडकर के 25 नवंबर के भाषण में हमेशा सामाजिक न्याय की वकालत की गई, और आगे कहा कि उन्होंने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाकर न्याय करने की जहाँ तक संभव हो सका, कोशिश की। भावुक होते हुए, गवई ने स्वीकार किया कि मेरी आवाज़ रुँधी हुई और भावनाओं से भरी हुई है, और उन्होंने अपने पेशेवर सफ़र को बेहद संतोषजनक बताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि न्यायाधीशों को अपनी भूमिका विनम्रता से निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश के तौर पर, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यह कोई शक्ति का पद नहीं, बल्कि कर्तव्य का पद है। मुख्य न्यायाधीश मनोनीत न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गवई की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके नेतृत्व की प्रशंसा की और उनकी आवाज़ को स्पष्ट, सिद्धांतबद्ध और निर्णायक बताया। उन्होंने आगे कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही महान संस्था है। सिर्फ़ जज ही नहीं, बल्कि पूरा सुप्रीम कोर्ट, बार, रजिस्ट्री और कर्मचारी ही फ़ैसले लेने में अहम भूमिका निभाते हैं।

आप ने साधा निशाना- समिति के बहाने जनता का ध्यान भटका रही बीजेपी, दिल्ली दम तोड़ रही

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार आठवीं दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति का राजनीतिकरण कर रही है। पार्टी ने एक बयान में कहा कि वह कई विशेष बैठकें बुलाकर और तथाकथित फर्जी घर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व अध्यक्ष राम निवास गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़ला को नोटिस जारी कर रही है। आप ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली के गहराते पर्यावरणीय संकट और चरमराती सार्वजनिक सेवाओं से ध्यान हटाने के लिए विधायी समितियों का हथियार बना रही है। आप ने विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही के मूल आधार पर ही सवाल उठाया। पार्टी ने कहा कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उद्धृत घटना अगस्त 2022 में सातवीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि वह विधानसभा फरवरी 2025 में भंग कर दी गई थी। एक बार विधानसभा भंग हो जाने पर, उसके विशेषाधिकार और कार्यवाही समाप्त हो जाती है। आठवीं विधानसभा पिछले कार्यकाल से संबंधित मामलों पर विशेषाधिकार प्राप्त कार्रवाई शुरू या जारी नहीं रख सकती। आप ने अमरिंदर सिंह बनाम पंजाब विधानसभा (2010) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया और कहा कि विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई कानूनी रूप से अस्थिर, प्रक्रियात्मक रूप से अस्थिर और पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। आप ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला है कि भाजपा सरकार ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण संकट की अनदेखी करते हुए विशेषाधिकार समिति की विशेष बैठक बुलाई। पार्टी ने कहा कि डॉक्टर अब सार्वजनिक रूप से परिवारों को सलाह दे रहे हैं कि अगर उनके छोटे बच्चे या बुजुर्ग सदस्य हैं तो वे दिल्ली छोड़ दें। इसमें आगे कहा गया है पूर्व एम्स निदेशक ने आगाह किया है कि दिल्ली में व्याप्त ज़हरीला धुआँ अब कोविड-19 से भी ज़्यादा मौतों का कारण बन रहा है।

उपराज्यपाल ने पुलिस को दिए निर्देश- अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री पर सख्त निगरानी की जाए

नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल ने लाल किला क्षेत्र में हाल ही में हुए विस्फोट के मद्देनजर, पुलिस को अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक रसायनों के निश्चित सीमा से अधिक की बिक्री का रिकॉर्ड बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। फरीदाबाद के धौज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को पकड़ने में कुछ और समय सुरक्षा एजेंसियों को लगता तो इनका नेटवर्क कई गुणा बढ़ सकता था। डॉ. मुजम्मिल, डॉ. उमर व डॉ. शाहीन आदि इस नेटवर्क को तेजी से फैला रहे थे। इस काम में उनकी मदद इलाके का मौलवी इश्तियाक मोहम्मद खुलकर करने लगा था। वह इलाके के रहने वाले 10 से अधिक लोगों की मुलाकात इस मॉड्यूल के डॉक्टरों से करा चुका था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के इस टेरर मॉड्यूल में फिलहाल सबसे अहम भूमिका डॉ. मुजम्मिल की थी। वो ही पाकिस्तानी हैंडलर से सबसे अधिक संपर्क में रहता था। उसी के पास हवाला नेटवर्क के जरिये रुपये आते थे। यहां तक कि विस्फोटक व

हथियार इकट्ठा कर उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर छुपाने की जिम्मेदारी भी डॉ. मुजम्मिल के पास ही थी। धौज और फतेहपुर तगा गांव के दोनों लोकेशन पर मिले 2900 किलो से अधिक विस्फोटक को उसने ही यहां छुपाया हुआ था। इन दोनों लोकेशन को उसने ही किराये पर लिया था। जांच एजेंसी के सूत्रों की माने तो धौज के रहने वाले सब्बीर को एनआईए ने हिरासत में लिया है। सब्बीर की गांव में ही मोबाइल की दुकान है। करीब 8 महीने पहले डॉ. मुजम्मिल अपना मोबाइल रिपेयर कराने सब्बीर की दुकान पर गया था। इसके बाद डॉ. मुजम्मिल कई बार धौज में सब्बीर की दुकान पर गया और यहीं से उसने कई मोबाइल सिम खरीदी थी। साथ ही, धौज के रहने वाले इकबाल मद्रासी से भी डॉ. मुजम्मिल ने बिना कोई आईडी दिए कमरा किराए पर लिया था। मद्रासी की मुलाकात अस्पताल में सितंबर महीने में बुखार की दवाई लेने के दौरान डॉ. मुजम्मिल से हुई थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, डॉ. शाहीन ने अपनी टीम में लड़कियों को शामिल करने का भी प्लान तैयार किया था। इसके तहत उसने कुछ लड़कियों की लिस्ट भी बनाई थी, जिसका जिक्र उसकी डायरी में भी है। इसके अलावा, किसको कितने पैसे की मदद करनी है, इसका फैसला भी डॉ. शाहीन और उमर नबी मिलकर ही करते थे। शाहीन लड़कियों की टीम बनाने में कामयाब नहीं हुई और वे यूनिवर्सिटी से किसी भी महिला डॉक्टर, स्टॉफ या छात्रा को अपने नेटवर्क में शामिल नहीं कर पाए।

डोनाल्ड ट्रंप-मोहम्मद बिन सलमान भू- राजनीतिक साझेदारी- स्वार्थ-प्रधान कूटनीति, रणनीतिक सौदे और बदलती वैश्विक शक्ति-संतुलन का विश्लेषण

वैश्विक स्तरपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच दिनांक 19 नवंबर 2025 को जब रही गलबहियां पूरी दुनियाँ ने देखी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी को प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी बता दिया है और एफ-35, परमाणु डील समेत कई महत्व समझौते किए हैं मध्य -पूर्व की राजनीति में खलबली मचा देने वाले इन दो देशों ने 1945 में भी एक महत्व समझौता किया था,जब एक युद्धपोत पर राष्ट्रपति फैंकलिन डी रूजवेल्ट और आधुनिक सऊदी किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद की मुलाकात हुई थी,इसी मुलाकात के बाद किसी समझौते की नींव रखी गई थी। वैश्विक राजनीति सदियों से राष्ट्रीय स्वार्थ और रणनीतिक लाभ के सिद्धांत पर संचालित होती रही है।जहां तक सामान्य बात के दौर कोविसतरवादी नीतियों हो, शीतयुद्ध काल के दो ध्रुवीय गठबंधन, या 21वीं सदी की आर्थिक-रणनीतिक कूटनीति, हर युग में महाशक्तियों ने अपनी प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखा। अभी हाल ही में एक दिन पूर्व डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) के बीच हुए ऐतिहासिक समझौतों निवेश के वायदों को भी इसी रूप में देखा जा सकता है। इन दोनों के बीच एक दिन पूर्व व्हाइट हाउसमें जो हुआ वह सिद्धांत की पुष्टि करता है कि राजनीति में स्थायी कुछ नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित स्थायी होते हैं। यह लेख इन दोनों नेताओं के हालिया व्हाइट हाउस संवाद,उससे जुड़े रणनीतिक व्यापारिक और सैन्य समझौतों तथा वैश्विक शक्ति समीकरणों पर पड़े प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि राजनीति में स्वार्थ की अवधारणा नई नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों केयथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, हर देश का सर्वोच्च उद्देश्य अपनी सुरक्षा, शक्ति और हितों की रक्षा करना होता है। यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी राष्ट्र,चाहे वह अमेरिका हो, सऊदी अरब हो या भारत,वैश्विक मंच पर उन्हीं निर्णयों को प्राथमिकता देता है,जिनसे उसका सामरिक, आर्थिक या राजनीतिक हित सुरक्षित हो।डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट और एमबीएस का विजन 2030 इसी स्वार्थ- प्रधान राजनीति के दो उदाहरण है। दोनों नेता इस धारणा पर चलते है कि बड़े फैसलेभावनाओं या सामूहिक नैतिकता के आधार पर नहीं,बल्कि कच्ची वास्तविकताओं, पैसा, सुरक्षा, निवेश, तेल, हथियार और वैश्विक प्रभाव के आधार पर लिए जाते है। साथियों बात अगर हम ट्रंप और एमबीएस-दो आक्रामक नेताओं की समान नीति-शैली कोसमझने की करें तो डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक राजनीति में अपनी लेन-देन आधारित कूटनीति (ट्रांसजेक्शनल डिप्लोमेसी) के लिए जाने जाते है। उनके शासनकाल में वैश्विक समझौते लाभ-हानि के कठोर आकलन पर आधारित थे। वे अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों पर पुनर्विचार करने,नाटो देशों से अधिक धन मांगने,चीन पर टैरिफ लगाने और पुराने समझौतों को रद्द करने में संकोच नहीं करते थे।इसी प्रकार मोहम्मद बिनसलमान अपने देश को आधुनिक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए तथा सुधारवादी नीति अपनाते है। सऊदी की तेल-निर्भर अर्थव्यवस्था को विविध बनाने, बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश लाने और मध्य-पूर्व की शक्ति-संतुलन में वर्चस्व बनाए रखने के लिए वे साहसिक कदम उठाते रहे है। उनके शासनकाल में सऊदी अरब ने क्षेत्रीय राजनीति में आक्रामक सैन्य और आर्थिक हस्तक्षेपों के माध्यम से खुद को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया है।दोनों नेताओं में तीन महत्वपूर्ण समानताएंदिखाई देती हैं(1)राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत (2) आक्रामक कूटनीति(3)बड़े आर्थिक और रक्षा सौदों पर जोर साथियों बात अगर हम ट्रंप- एमबीएस व्हाइट हाउस बैठक- भू-राजनीतिक हलचल का केंद्र इसको समझने की करें तो, 2018 के बाद पहली बार एमबीएस का अमेरिका आगमन और व्हाइट हाउस में ट्रंप द्वारा किया गया ऐतिहासिक स्वागत वैश्विक मीडिया का केंद्र बन गया यह केवल एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरणों को पुनर्परिभाषित करने वाला क्षण था।इस मुलाकात के कई अर्थ थे- (1)सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में आई ठंडक अब समाप्त हो रही है।(2) बाइडेन प्रशासन के तहत मौजूद तनाव और अविश्वास अब इतिहास बनता दिख रहा है।(3) मध्य-पूर्व में अमेरिका अपनी प्रभावशीलता पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

(4) एमबीएस की अंतरराष्ट्रीय छवि, जो खशोगी प्रकरण में धूमिल हुई थी, ट्रंप ने उसे पुनः वैधता प्रदान कर दी।ट्रंप के इस कदम को विश्लेषक व्यवहारिक कूटनीति कहते है,जहाँ मानवीय अधिकारों का मुद्दा पीछे छूट जाता है और व्यापार, हथियार सौदे तथा रणनीतिक प्रभाव प्राथमिकता बन जाते हैं। साथियों बातें कर हम सऊदी को मेजर नॉन-नाटो एली का दर्जा और अभूतपूर्व रक्षा सौदे इसको समझने की करें तो इस बैठक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय था सऊदी अरब को मेजर नॉन-नाटो एली का दर्जा देना।यह दर्जा सामान्यतः उन देशों को मिलता है जो अमेरिका के दीर्घकालिक रक्षा-सहयोगी होते हैं। इससे सऊदी को अमेरिकी तकनीक, हथियार, रक्षा सहयोग, खुफिया सूचना और सुरक्षा साझेदारी के विशेष अधिकार प्राप्त होंगे।यह कदम मध्य-पूर्व में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा।इसके साथ ही दो बड़े रक्षा समझौते घोषित हुए(1) 48 एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट की बिक्री-एफ -35 दुनिया का सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक स्टील्थ विमान है।सऊदी के लिए यह एक "गेम-चेंजर" सिद्ध होगा।यह इजरायल, ईरान और तुर्किये जैसे देशों के सैन्य समीकरणों पर गहरा असर डालेगा। (2) 300 अब्राम्स टैंक की बिक्री-अब्राम्स एम 1ए 2 टैंक दुनिया की सबसे उन्नत स्थलीय युद्ध मशीनों में गिना जाता है।इससे सऊदी की थलसेना का सामरिक शक्ति- संतुलन कई गुना बढ़ जाएगा।इन दोनों सौदों के पीछे ट्रंप का साफ संदेश है-बिजनेस इज बिजनेस, और अमेरिका का हित सर्वोपरि है। साथियों बात अगर हम सऊदी का अमेरिका में ऐतिहासिक निवेश,एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य इसको समझने की करें तो,एमबीएस ने अमेरिका में सऊदी अरब के निवेश को बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने की घोषणा करके वैश्विकआर्थिक जगत में हलचल मचा दी। यह रकम पहले से घोषित 600 अरब डॉलर के निवेश से कहीं अधिक है। उन्होंने अमेरिका को दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बताया, जो स्पष्ट करता है कि सऊदी आर्थिक रूप से अमेरिका पर भरोसा बढ़ा रहा है। यह निवेश केवल आर्थिक नहीं, बल्कि 3 बड़े रणनीतिक उद्देश्यों को साधता है (1) अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सऊदी की निर्णायक भागीदारी(2)द्विपक्षीय संबंधों को विशेष आधार पर मजबूती (3) ट्रंप प्रशासन को समर्थन और सुरक्षा गारंटी प्राप्त करना,एफ -35 और 300 अब्राम्स टैंकों के अतिरिक्त सऊदी द्वारा 88 लाख करोड़ (अरबों डॉलर) की डील अमेरिकी उद्योग के लिए बड़ी आर्थिक संजीवनी है।

सम्पादकीय...

जुर्म की डगर

दिल्ली में चोरी से लेकर हत्या तक ऐसी घटनाएं आम है जिसमें आरोपी नाबालिग होते है। ऐसी ही एक और घटना सामने आई है। विजय विहार इलाके में पांच नाबालिगों ने एक ऑटो ड्राइवर की हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि लूट का विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से गोदकर हत्या को अंजाम दिया। मृतक की पहचान 52 वर्षीय राकेश कुमार के रूप में हुई है। इस बाबत विजय विहार थाने में हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पांचो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। हाल ही में 10 नवंबर को भी एक घटना सामने आई थी, जिसमें भलस्वा डेयरी इलाके में एक युवक को उसी के ई-रिक्शा में छलकर लड़कों का एक ग्रुप ले गया था। इसके बाद उस युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पांच आरोपियों को पकड़ लिया था। इस हमले को अंजाम देने वाले आरोपियों में 3 नाबालिग थे, जिनकी उम्र 16, 14 और 16 थी। दिल्ली को लेकर आई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट डराने वाली है। यहां नाबालिग अब नए क्रिमिनल बनकर उभर रहे हैं। आंकड़ों से पता चला है कि जनसंख्या कम होने के बावजूद, नाबालिगों (माइनर्स) की ओर से किए गए अपराधों के मामले में दिल्ली अब देश में पांचवें स्थान पर आ गया है। वहीं मेट्रो शहरों से तुलना करें तो ये टॉप पर है। इसने उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। राजधानी के नाबालिग अब तेजी से संगठित अपराधों की ओर मुड़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, चोरी और लूटपाट अभी भी सबसे आम अपराध है लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अब अपराध का पैटर्न (तरीका) बदल रहा है। एक वरिष्ठ दिल्ली पुलिस अधिकारी ने कहा, -पिछले तीन सालों में शहर में नाबालिगों के अपराध बहुत चिंताजनक हो गए हैं। पहले वे असंगठित तरीके से काम करते थे और ज्यादातर चोरी और लूटपाट तक ही सीमित थे लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नाबालिग गिरोह बना रहे हैं और उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण दिल्ली में सक्रिय बड़े आपराधिक नेटवर्क के साथ मिलकर अपराध कर रहे हैं। साल 2023 में कुल 4,098 किशोरों को पकड़ा गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चला है कि इन किशोरों की शिक्षा का स्तर कुछ इस प्रकार था- शिक्षा का स्तर किशोरों की संख्या पूरी तरह से अनपढ़ (कभी स्कूल नहीं गए) 381 प्राइमरी स्तर तक पढ़े (जल्दी स्कूल छोड़ा) 995 कक्षा 10 तक पढ़े (सबसे बड़ा समूह)1,432 कक्षा 12 तक पढ़े, 246 उच्च माध्यमिक से आगे की पढ़ाई की। यह आंकड़ा रोचक है क्योंकि यह इस धारणा को तोड़ता है कि सभी अपराधी अनपढ़ होते हैं। वास्तव में, अधिकांश ने कक्षा 10 तक पढ़ाई की है और उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। इन आंकड़ों से यह भी सामने आया कि पकड़े गए 2,640 किशोर अपने माता-पिता के साथ रहते थे, 334 अभिभावकों के साथ और केवल 124 बेघर थे। जानकारों के मुताबिक नाबालिगों द्वारा बढ़ते अपराध की वजह मौजूदा शहरीकरण और औद्योगीकीकरण की प्रक्रिया से निर्मित संवेदनहीन माहौल है। ऐसे माहौल के कारण ज्यादातर परिवार अपने बच्चों को काबू में रखने में विफल हो रहे हैं। निजी आजादी में बढ़ोतरी से नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं। अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चों की स्वाभाविकता छिन गई है। वे गुस्सैल और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। कम्प्यूटर और इंटरनेट ने नाबालिगों को समाज और परिवार से अलग-थलग कर दिया है। वे अवसाद के शिकार होने लगे हैं और अपराध की दुनिया में भी छलांग लगा लेते हैं। इन कारणों से नाबालिग अपराध के क्षेत्र में सक्रिय रहने लगे हैं। बच्चा वही सिखता है जो उसके आसपास घटित होता है। कोरोना काल में बच्चों की मनोदशा पर अधिक प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह है ऑनलाइन गेमिंग व मेल-जोल का कम होना। बच्चे आजकल मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग में अधिक व्यस्त है। इसमें भी बच्चों को आक्रोश वाले गेम अधिक पसंद है जिससे बच्चों की मनोदशा बदलती है। अपराध की कोई श्रेणी नहीं है। एक पढ़े-लिखे बच्चे से लेकर स्लम में रहने वाला कम शिक्षित या अनपढ़ बच्चा संगीन अपराध के लिए तैयार हो जाता है। उन्हें अपराध से मुक्त बनाए रखने के लिए केवल सरकार के भरोसे रहना भारी भूल होगी। समाज और घर परिवार को भी सचेत होने की जरूरत है। नाबालिगों द्वारा किए जा रहे यौन अपराधों की शिकार महिलाएं और युवतियों के साथ बच्चियां भी हो रही हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 'भारतीय दण्ड संहिता' के तहत दर्ज नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 47 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। नाबालिग होते हुए भी वे बालिगों जैसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगे हैं और नाबालिगों को दी जाने वाली छूट का लाभ उठाकर और भी खूंखार अपराधी बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि बालिग अपराधियों जैसे गंभीर अपराध करने के बावजूद नाबालिग अपराधी कठोर दंड से बच जाते हैं। वर्ष 2012 के 'निर्भया बलात्कार कांड' में पीड़ित लड़की के साथ सबसे अधिक दरिंदगी करने वाला नाबालिग अपराधी मृत्यु दण्ड से बच गया, जबकि इसी बलात्कार कांड में बाकी के सभी बालिग अपराधियों को फांसी दी गई। गंभीर अपराधों में संलिप्त नाबालिगों को लेकर कानून अस्पष्ट और लचर होने का ही परिणाम है कि उनका दुस्साहस लगातार बढ़ता चला गया है। यह देखा गया है कि जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले कई नाबालिगों पर बाल सुधार गृह में भेजने का भी कोई असर नहीं होता। खासतौर पर सुनियोजित तरीके से हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों के नाबालिग आरोपियों के प्रति क्या नीति अपनाई जानी चाहिए, अब इस मसले पर सरकार और समाज को एक बार विचार करना होगा। जाहिर है, नाबालिगों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति को रोक पाना अकेले कानून के बस में नहीं है। अभी किशोर न्याय बोर्ड केवल 16 से 18 वर्ष के नाबालिग आरोपितों के मामले में बालिग की तरह केस चलाने की प्रार्थना पर विचार कर सकता है लेकिन बदलते समय में कानून के इस प्रविधान में संशोधन की जरूरत महसूस होती है। नाबालिगों द्वारा अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त हर आयु के नाबालिग से सख्ती से निपटना चाहिए। अगर उसकी प्रवृत्ति आपराधिक पाई जाती है।

आतंकवाद की ओर जा रहे हैं कुछ डाक्टर

मैडिसिन के डाक्टर हमेशा से हमारे कामों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहे हैं, जिनकी इस दुनिया में हर इंसान तारीफ करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी डाक्टर की जरूरत न पड़ी हो। डाक्टरों को नेक इंसान माना जाता है जो दूसरे इंसानों को जिंदा और ठीक रखने की फिक्र करते हैं। 10 नवंबर,2025 को दिल्ली में लाल किले के पास मैट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके में 13 आदमी मारे गए और कई आदमी और औरतें घायल हो गईं, यह न सिर्फ हमारी मजबूत सरकार के लिए बल्कि हमारे देश के आम लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका था। पाकिस्तान में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक टैरर मॉड्यूल का पता चला। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग डाक्टर हैं। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? आम आदमी ऐसे टैरर मॉड्यूल की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें एक डाक्टर भी शामिल हो। अब उसे बताया जा रहा है कि इस खास मॉड्यूल में ज्यादातर डाक्टर हैं जो सभी इस्लाम को मानते है लेकिन जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और बंगाल जैसे अलग-अलग राज्यों से हैं। सिर्फ सबसे होशियार स्टूडेंट ही मैडिकल कॉलेज में सीट पक्की कर सकते हैं। पढ़ाई साढ़े 5 साल की होती है और अगर स्टूडेंट मैडिसिन की किसी भी ब्रांच में स्पैशलाइज करना चाहता है तो उसे 2 साल या उससे ज्यादा और लगेंगे, जिसके बाद जरूरी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी होगी। जिन डॉक्टरों ने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल ऐसी जिंदगी की तैयारी में बिताए हैं जो दूसरों को जिंदा रहने में मदद करती है, वे अपना मकसद क्यों छोड़कर सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को मैसेज देने के लिए बेगुनाह लोगों को मारने और घायल करने पर उतर आए? इसका जवाब पिछले कुछ सालों में खोजे गए दूसरे टैररिस्ट मॉड्यूल में मिल सकता है। अभिनव भारत एक अकेला मॉड्यूल था जो हैरानी की बात है कि ज्यादातर कम्युनिटी में घुसा हुआ था, जिसे महाराष्ट्र के एंटी-टैररिस्ट स्क्वॉड ने खोजा था। पॉलिटिकल फील्ड में फायदेमंद पोजीशन वाले लोगों में भी जो गहरा गुस्सा था, उसे हमें अपने मन की आंखों में, उन लोगों तक पहुंचाना होगा जो इस समीकरण के शिकार थे। जब भारत के इकलौते मुस्लिम-बहुल राज्य को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और उन लोगों ने उसे कमतर दर्जा दिया, जिन्हें उसका सैक्युलर और बराबरी के रैंक में स्वागत करना चाहिए था, उसे बुरी तरह याद दिलाया गया कि उस पर कभी भरोसा नहीं किया जाएगा तो दुश्मनी और नफरत को पनपने के लिए जमीन तैयार हो गई। मोदी-शाह की जोड़ी का मजबूत गवर्नेंस मॉड्यूल जम्मू-कश्मीर में अपने तख्तापलट की शेखी बघारता रहा। राज्य में और ज्यादा सैनिक और पैरा-मिलिट्री भेजी गई, इस उम्मीद में कि बॉर्डर पार से आतंकवाद और कश्मीरियों के बीच अलगाववादी तत्व बेअसर हो जाएंगे। शुरू में ऐसा सरप्राइज फैक्टर की वजह से हुआ। राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मुश्किल और हमेशा रहने वाली हिंदू-मुस्लिम समस्या को बहुत सोच-समझकर और बारीकी से सुलझाया था। उन्होंने पूर्व रॉ चीफ ए.एस. दुलत पर भरोसा किया, जिन्होंने फारूख अब्दुल्ला के साथ पक्की दोस्ती की थी। अब्दुल्ला परिवार ही काफी हद तक कश्मीरी मुसलमानों के भारत के साथ अपने मुस्लिम-बहुल पड़ोसी पाकिस्तान के साथ इलाके के झगड़े में साथ देने के लिए जिम्मेदार रहा है। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार कुछ और ही सोचती थी। उसने कश्मीरी मुसलमानों को दबाने के लिए आक्रामकता का इस्तेमाल करने का फैसला किया और अपने ही वोटरों को यह साबित करने का फैसला किया कि वह कांग्रेस और यहां तक कि वाजपेयी की भाजपा सरकार के उलट एक मजबूत और ताकतवर सरकार है। ऐसा तरीका शायद ही कभी काम करता है। अगर वहां के लोग भाईचारे की उम्मीद को पसंद नहीं करते हैं तो भारतीय सरकार या कोई भी राज्य हथियारों के बल पर राज नहीं कर सकता। ऐसी जगहों पर आतंकवाद पनपता है। लाल किले में हुए धमाके के कुछ मुख्य साजिशकर्ता साऊथ कश्मीर के पहलगाम से हैं, जहां पहले से बदनाम आई.एस.आई. के प्लान किए गए आतंकी हमले की खबर आई थी। 'ऑपरेशन सिंदूर' हमारा कामयाब जवाब था। हमारी एयर फोर्स और सपोर्टिंग ग्राऊंड फोर्स ने हमारे पड़ोसी के इलाके में आतंकियों के कई ठिकानों को खत्म करके अपना काम ठीक से किया। बदकिस्मती से, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना जोश रोक नहीं पाए और खुलेआम धमकी दी कि अगर हमारे पड़ोसी ने कभी बॉर्डर पार अपने आतंकी शागिर्दों को भेजने की हिम्मत की तो वे 'ऑपरेशन सिंदूर' दोहराएंगे। न तो लड़ने वाले पड़ोसी और न ही दुनिया की बड़ी ताकतें इंडियन सब-कॉन्टिनेंट में कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी के नतीजों को मान पाएंगी। 10 नवंबर को लाल किले के बाहर दिल्ली में हुए धमाके के बाद, यू.एस. सैक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने शायद बिना कोई कीमती समय बर्बाद किए दिल्ली में अपने समकक्ष से बात की। उन्होंने अगले ही दिन एक बयान जारी कर भारत के 'सोचे-समझे जवाब' और देश के अंदर आतंकी मॉड्यूल की पहचान करने में हमारी कामयाबी की तारीफ की। उन्होंने देश के कानून के हिसाब से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अपने देश का सपोर्ट जताया। उनके बयान की लाइनों के बीच यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक और 'ऑपरेशन सिंदूर' के खिलाफ भी सलाह दी। जो मॉड्यूल मिला है, उसने पूरे भारत में और भी कई हमलों की प्लानिंग की थी। इसके जाल हरियाणा और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बहुत आगे तक फैले हुए थे, जहां यह पनप रहा था। कम से कम एक बड़ा काम तो अभी हो गया है क्योंकि 8 छोटे मॉड्यूल को खत्म कर दिया गया है लेकिन आने वाले समय में भी लड़ाई जारी रहेगी। भारत के दो बड़े समुदायों के बीच अविश्वास और गलतफहमी तब से है जब से इस्लामिक सेनाएं हिंदू कुश के रास्ते सब-कॉन्टिनेंट में आई हैं और मैं कह सकता हूं कि यह दुश्मनी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी।-जूलियो रिबैरो (पूर्व डी.जी.पी. पंजाब व पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी)।

भ्रष्टाचार और जंगलराज से समझौता बना कांग्रेस की हार का कारण

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की विशेष अदालत ने पिछले महीने आई.आर.सी.टी.सी. होटल घोटाला मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सी.बी.आई. के अनुसार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आई.आर.सी.टी.सी. अधिकारियों, कोचर बंधुओं समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए थे। यह खबर पूरे देश में पढ़ी-सुनी गई। यदि किसी ने नहीं देखी तो वह है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने लालू यादव के भ्रष्टाचार और जंगलराज के अन्य मामलों की तरह इसे भी नजर अंदाज कर दिया। कांग्रेस यह भूल गई कि यदि ऐसे मामलों को अनदेखी की गई तो मतदाता भी उसे भूल जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में यही हुआ। मतदाता भूल गए कि कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय और प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है। कांग्रेस ने सत्ता के लिए भ्रष्टाचार से समझौता किया। मतदाताओं ने कांग्रेस के इस रवैये को मतों से ठुकरा दिया। सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस ने पिछली गलतियों से जरा भी सबक नहीं सीखा। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था आज भी देश में प्रमुख मुद्दा है। विकास और दूसरे मुद्दे इसकी नींव पर खड़े होते है यदि नींव ही कमजोर होगी तो विकास की इमारत नहीं टिक पाएगी। कांग्रेस ने बिहार में लालू यादव की पार्टी से सत्ता के लिए समझौता कर अपने पैरों पर फिर से कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कांग्रेस को बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से मात्र 6 सीटें मिलीं। इस शर्मनाक हार की जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। कांग्रेस अब इस जिम्मेदारी से भागने के लिए फिर से वही पुराना वोट चोरी, सरकारी मशीनरी के चुनाव में दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। अभी भी कांग्रेस इस सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं है कि उसने एक महाभ्रष्ट लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से सीटों का समझौता करके भारी भूल की है। बिहार के मतदाताओं ने इन दोनों दलों को तगड़ा सबक सिखाया है। कांग्रेस ने आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे लालू परिवार के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने का गलत निर्णय लिया। यह जानते हुए भी कि मतदाता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपराधी परिवार के साथ चुनावी तालमेल की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ गई। भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और जंगलराज को प्रमुख मुद्दा बनाया। कांग्रेस इसके बचाव में कोई दलील देकर मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर सकी। बिहार में चुनाव हो और चारा घोटाले से जुड़ी कहानियां सामने न आएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये घोटाला ही ऐसा था कि 30 साल बाद भी लोग इसके बारे में बात करते हैं और जानने की चाहत रखते हैं। कांग्रेस ने 950 करोड़ रुपए के घोटाले में अपने प्रमुख सहयोगी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पर्दे के पीछे से राजनीतिक चालें चलीं लेकिन वे असफल रहीं। वर्ष 1990-96 के दौरान सामने आया चारा घोटाला बिहार पशुपालन विभाग में हुआ। यह घोटाला मुख्य रूप से 1990 के दशक में हुआ।

भारत-अमेरिका एलपीजी ऊर्जा सहयोग -टैरिफ तनाव कूटनीतिक संतुलन और वैश्विक व्यापार

वैश्विक स्तर पर भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा व्यापार, विशेष रूप से एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) के क्षेत्र में हुआ नया समझौता न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भू-राजनीतिक समीकरणों, टैरिफ युद्ध, कृषि बाजारों में प्रवेश,और वैश्विक व्यापार नीतियों के बदलते ढांचे का संकेत भी देता है। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों में कभी सहयोग तो कभी तनाव की स्थिति देखने को मिली है,विशेषकर जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए थे। ऐसे माहौल में एक वर्ष के लिए किया गया यह विशाल एलपीजी आयात समझौता द्विपक्षीय रिश्तों में सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावना की गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूंकि यह समझौता भले ही भारत की कुल वार्षिक आवश्यकता का मात्र 10 प्रतिशत है,लेकिन इसकी कूटनीतिक भाषा और रणनीतिक संदेश कहीं अधिक बड़े हैं।भारत घरेलू ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, वहीं अमेरिका को भारतीय बाजार में एक नई तकनीकी और व्यावसायिक एंट्री मिल रही है। इसके साथ ही यह समझौता भविष्य में संभावित ट्रेड डील,टैरिफ घटाने, और भारत-अमेरिका संबंधों के सुधार का संकेत माना जा रहा है। साथियों बातें अगर हम भारतीय किचन में 'मेड इन अमेरिका' एलपीजी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार का नया आयाम इसको समझने की करें तो,भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है, जहाँ घरों में एलपीजी का उपयोग सबसे तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत के लगभग 90 प्रतिशत घरों में एलपीजी का उपयोग होता है, और इनमें से 65 प्रतिशत एलपीजी आयात की जाती है। भारत की घरेलू जरूरतों का केवल 35 प्रतिशत ही देश में उत्पादित होता है। इसलिए ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने और आपूर्ति के जोखिम को कम करने के लिए भारत के लिए एलपीजी आयात में नए स्रोत जोड़ना रणनीतिक रूप से अनिवार्य था।अमेरिका दुनियाँ का बड़ा शेल गैस उत्पादक है और वह ऊर्जा निर्यात का विस्तार करना चाहता है। इस संदर्भ में भारत द्वारा अमेरिका से 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात के लिए किया गया एक-वर्षीय समझौता न केवल व्यापारिक है,बल्कि रणनीतिक भी है। यह समझौता अमेरिका को भारतीय ऊर्जा बाजार में पहली वास्तविक एंट्री देता है। अमेरिका लंबे समय से चाहता था कि भारत उसके कृषि उत्पादों, विशेष रूप से गेहूं, मक्का, सोया और डेयरी के लिए अपना बाजार खोले। लेकिन भारत कृषि क्षेत्र में संवेदनशीलता और लाखों किसानों की आजीविका को देखते हुए इसे अनुमति देने से लगातार बचता रहा है।परिणाम स्वरूप अमेरिका ने नाराज होकर भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ा दिया।अब एलपीजी समझौता अमेरिका को 'एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक एंट्री' देता है, जिससे ट्रंप प्रशासन के व्यापार तनाव को कम करने और भविष्य में बड़े समझौतों की दिशा में बढ़ने की संभावना दिखती है। साथियों बात अगर हम भारत- अमेरिका एलपीजी समझौता- एक वर्ष का अनुबंध लेकिन भविष्य के व्यापक व्यापारिक सहयोग की नींव समझने की करें तो,नई डील के अनुसार भारत अमेरिका से लगभग 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा। यह मात्रा भारत की सालाना एलपीजी खपत का केवल 10 प्रतिशत है, लेकिन इसकी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक महत्ता इससे कहीं अधिक है।यह समझौता महत्वपूर्ण क्यों है? यह पहली बार है जब अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में भारत के घरेलू बाजार में सीधे प्रवेश कर रहा है। यह समझौता एक वर्ष के लिए है, लेकिन इसे बड़े, दीर्घकालिक समझौते की पृष्ठभूमि माना जा रहा है।टैरिफ विवादों के बीच यह दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में कदम है।इससे यह संकेत मिलता है कि भारत अब अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका, के साथ अधिक सुरक्षित करना चाहता है।यह सौदा भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के नए युग की शुरुआत कर सकता है, जहाँ अमेरिका ऊर्जा निर्यात को बढ़ाएगा और भारत आयात स्रोतों में विविधता लाएगा। इसके साथ ही भारत ने यह संदेश भी दिया है कि वह अमेरिका को अपने बाजार में प्रवेश तो देगा, लेकिन कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं। साथियों बात अगर हम भारत का एलपीजी पर बढ़ता आयात-घरेलू ऊर्जा नीति, उज्ज्वला योजना और खाड़ी देशों से निर्भरता इसको समझना की करें तो, पिछले एक दशक में भारत में एलपीजी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है,सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत करोड़ों गरीब परिवारों को सब्सिडी पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इससे ग्रामीण और कम आय वाले परिवार भी खाना पकाने के लिए सुरक्षित ईंधन की ओर बढ़े हैं।भारत के प्रमुख एलपीजी आयात स्रोत (2024) यूएई- 81लाख टन, कतर-50 लाख टन,कुवैत, सऊदी अरब, महत्वपूर्ण मात्रायह है इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत की एलपीजी सप्लाई खाड़ी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है। भू-राजनीतिक तनाव, युद्ध, शिपिंग रूट में खतरों और कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए भारत को नए आयात स्रोतों की आवश्यकता थी। ऐसे में अमेरिका से एलपीजी आयात भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा के लिहाज से एक मजबूत कदम है।इसके साथ ही यह समझौता संदेश देता है कि भारत, ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाए जाने के बावजूद, संबंधों को नए सिरे से संतुलित करना चाहता है।यह डील इस तथ्य को भी इंगित करती है कि अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद भारत और अमेरिका दोनों एक-दूसरे के लिए बड़े बाजार बने रहेंगे। अमेरिका के लिए भारत ऊर्जा निर्यात और अन्य टेक्नोलॉजिकल डील्स का बड़ा केंद्र है। साथियों बातें कर हम क्या एलपीजी समझौते से खुलेगा ट्रेड डील का रास्ता? मोदी-ट्रंप समीकरण में संभावित बदलाव इसको समझने की करें तो,यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या यह एलपीजी समझौता भारत और अमेरिका के बीच व्यापक ट्रेड डील का मार्ग प्रशस्त कर सकता है? विशेषज्ञों और कूटनीतिज्ञों के अनुसार, इसके तीन प्रमुख संकेत हैं(क) विश्वास बहाली की शुरुआत-टैरिफ विवादों, कृषि बाजार तनाव और रूस से ऊर्जा खरीद पर अमेरिका की नाराजगी के बाद दोनों देशों में अविश्वास बढ़ गया था। इस एलपीजी समझौते से विश्वास की वापसी की शुरुआत मानी जा रही है।

-(ख) अमेरिका को भारतीय बाजार में सीमित प्रवेश-भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रवेश न मिल पाने की निराशा को कम करने के लिए अमेरिका को ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश मिला। यह रणनीतिक रूप से संतुलित नीति है। भारत ने कृषि बाजार नहीं खोला, लेकिन एलपीजी जैसे गैर-संवेदनशील क्षेत्र में सौदा किया।यह भविष्य के बड़े व्यापारिक समझौतों की तैयारी जैसा है।(ग) मोदी- ट्रंप समीकरण का व्यावहारिक पहलू-ट्रंप और मोदी के बीच पिछले समय में मजबूत व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, लेकिन वैश्विक व्यापार में ट्रंप की नीति हमेशा -अमेरिका फर्स्ट- रही है। ट्रंप ने बार-बार कहा कि भारत -उच्च टैरिफ वाला राष्ट्र- है।अब भारत द्वारा किया गया यह समझौता संकेत देता है कि मोदी सरकार टैरिफ तनाव कम करने और अमेरिका के साथ ऊर्जा आधारित आर्थिक साझेदारी बढ़ाने की इच्छुक है।कई विश्लेषकों का मानना है कि यह डील भविष्य में टैरिफ खत्म करने, नए क्षेत्रीय सहयोग, और संभवतः नवीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए)-जैसी संरचना की शुरुआत कर सकती है। साथियों बात अगर हम रूस से ऊर्जा खरीद पर अमेरिकी टैरिफ और भारत-अमेरिका व्यापार के सामान्य स्थिति लौटने की संभावना इसको समझने की करें तो अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर रूस से ऊर्जा खरीदने के कारण 25प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुँच गया।यह कदम अमेरिका द्वारा भू-राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका था।

उन्हें उम्मीद थी कि भारत रूस से ऊर्जा आयात कम करेगा। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता है, और वह अपने हितों के अनुसार आयात नीति तय करेगा।अब एलपीजी डील के बाद यह संभव है कि अमेरिका भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ कम करे,दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापारिक संबंध बहाल हों,ऊर्जा व्यापार सहयोग नए उच्च स्तर पर पहुँचे,विशेषज्ञ मानते हैं कि यह डील एक द्विपक्षीय राजनीतिक संदेश भी है-भारत रूस से ऊर्जा खरीदता रहेगा, लेकिन साथ ही अमेरिका के साथ भी ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने को तैयार है।भारत ने इससे वैश्विक संतुलन की अपनी नीति को दोबारा स्थापित किया है, बहु-आयामी व्यापार और संतुलित कूटनीति।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/40882)

डीएम ने मण्डी स्थित भारतीय खाद्य निगम के धान क्रय केन्द्र का किया निरीक्षण

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चिन्हित स्ट्रांग रूम का लिया जायजा

बहराइच।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत जनपद में की जा रही धान खरीद का जायज़ा लेने तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु मतपत्रों को सुरक्षित रखने हेतु बनाये गये स्ट्रांग रूम का जायज़ा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कृषि उत्पादन मण्डी समिति सलारपुर बहराइच का निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम के लिए चिन्हित कक्षों का निरीक्षण करते हुए डीएम ने सचिव मण्डी को आवश्यक रंग-रोगन व मरम्मत कराये जाने के निर्देश दिये गये। मण्डी समिति के भ्रमण के दौरान डीएम श्री त्रिपाठी ने भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय केन्द्र प्रभारी अनुज शुक्ला उपस्थित मिले। खरीद की बाबत केन्द्र प्रभारी ने बताया कि अब तक 24 किसानों से 1213.60 कु. धान खरीद की गयी है। निरीक्षण के समय ग्राम टेंड़िया के कृषक केशव सिंह के उपज की तौल हो रही थी। केन्द्र पर खरीद सम्बन्धी समस्त व्यवस्थायें पूर्ण पायी गयी। डीएम द्वारा केन्द्र प्रभारी को निर्देशित किया गया कि केन्द्र का सुचारू संचालन कर अधिक से अधिक किसानों से धान की खरीद की जाय। डीएम ने मण्डी सचिव को निर्देश दिया कि मण्डी में संचालित केन्द्रों पर उपकरण आदि की समुचित व्यवस्था रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर धान खरीद करायें। मण्डी आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। डीएम द्वारा मण्डी सचिव धनंजय सिंह को निर्देशित किया गया कि मण्डी में समस्त केन्द्रों पर उपकरण आदि की समस्त व्यवस्थापूर्ण कराते हुए मण्डी के भी केन्द्रों पर धान खरीद सुनिश्चित करायें। मौके पर मौजूद खाद्य एवं विपणन अधिकारी रूपेश सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत जनपद हेतु 205000 मी.टन धान खरीद का लक्ष्य आवंटित है। जनपद में 06 क्रय एजेन्सियों के 135 धान क्रय केन्द्र अनुमोदित /संचालित हैं। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई

बहराइच।

यातायात माह जागरूकता अभियान के तहत एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्राधिकारी कैसरगंज रवि खोखर की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक और अध्यापकों की उपस्थिति में छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय प्रांगण में एकत्र हुए बच्चों को सड़क पार करने के सुरक्षित तरीके, यातायात लाइटों के संकेतों का महत्व, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग और दोपहिया पर तीन सवारी न बैठने जैसे नियमों की जानकारी दी गई। उन्हें सड़क पर लगे यातायात संकेतों का पालन करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने के लिए भी जागरूक किया गया। इस दौरान, स्कूल प्रबंधक को स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, यथाशीघ्र बसों की चेकिंग करने के लिए भी कहा गया ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कोतवाली कैसरगंज के प्रभारी निरीक्षक बृजेन्द्र मिश्र ने बताया कि यातायात नियमों का पालन करना दुर्घटनाओं को रोकने और सभी के लिए सुरक्षित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में यातायात सिग्नल और लाइटें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं,जिससे यातायात प्रवाह सुचारु बना रहता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सड़क सुरक्षा के महत्व को बढ़ाना है।

गाड़ी चलाते समय मोबाइल उपयोग न करने, हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने पर जोर

एंबुलेंस में हुआ प्रसव जच्चा बच्चा स्वस्थ, अस्पताल में भर्ती

बहराइच।

एबुलेंस में गुंजी किलकारी, पूनम देवी पत्नी माधव निवासी गोबरहा हुजूरपुर थाना जिला बहराइच अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई जिसकी जिसकी जानकारी पारिवारिक जन को हुई और तुरंत परिवार के लोगों द्वारा 108 नंबर पर सूचित किया जिसकी सूचना 108 एंबुलेंस नंबर यूपी32EG0592 को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही एंबुलेंस पर तैनात ईएमटी प्रिंस कुमार त्रिपाठी व पायलट वीरेंद्र सिंह बड़ी सजकता से एंबुलेंस सीन पर लेकर पहुंचे वहां पर बड़े तत्परता से मरीज को एंबुलेंस में शिफ्ट कराया अस्पताल ले जाते समय प्रसव पीड़ा अधिक होने पर एमटी प्रिंस कुमार त्रिपाठी ने रास्ते में एंबुलेंस रोक करके परिवारजन की मदद से सुरक्षित प्रसव कराया जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है और प्रसव पश्चात ले जाकर सुरक्षित जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती करवाया परिवार जनों में खुशी का माहौल है।

ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी

मुरादाबाद।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) संगीता गौतम ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 की पूर्व निर्गत अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए वृहद पुनरीक्षण का कार्य समय सारणी के अनुसार सम्पन्न कराए जाने हेतु समस्त उपजिलाधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार (निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही) दिनांक 10 दिसम्बर 2025 तक की जाएगी, निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमाकंन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिंग, फोटोप्रतियां कराने की तिथि 11 दिसम्बर से 22 दिसम्बर 2025 है, आलेख्य प्रकाशन के रुप में प्रकाशित अनन्तिम मतदाता सूची के निरीक्षण की तिथि 24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2025 है, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने (01 जनवरी 2026 से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किए जाएंगे) की तिथि 24 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2025 तक, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की तिथि 31 दिसम्बर 2025 से 06 जनवरी 2026 तक है, दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियां तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय में जमा करने की अवधि 07 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक है, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थल समाहित करने की कार्यवाही की तिथि 13 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक है, पूरक सूचियों के कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमाकंन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां कराने की तिथि 30 जनवरी से 05 फरवरी 2026 तक एवं निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन की तिथि 06 फरवरी 2026 निर्धारित है।

विधायक ने किया राशन कार्डो का वितरण

मुरादाबाद।

ब्लॉक सभागार कुंदरकी एवं ब्लॉक सभागार मूंढापांडे में राशन कार्ड वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के जनसहयोग कार्यालय में प्राप्त आवेदनों में पात्रता की बुनियाद पर पूर्ति विभाग द्वारा सत्यापन के पश्चात कुंदरकी ब्लॉक में 260 लाभार्थियों और मूंढापांडे ब्लॉक में 270 लाभार्थियों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड वितरित किये गए। इस अवसर पर कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि एक वर्ष से लगातार वंचितों के राशन कार्ड मेरे द्वारा बनवाये जा रहे है। केंद्र सरकार की तरफ से फ्री राशन की व्यवस्था कोविड काल से लगातार चल रही है, जोकि इसी प्रकार से आगे भी जारी रहेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नीति है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को सरकारी योजनाओं में बराबर का हिस्सा मिले। कोई जरूरतमंद सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। समाज के हर जरूरतमंद तक सुविधाएं पहुँचाने का मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। राशन कार्ड धारक भी इस बात का ध्यान रखे कि अगर उन्हें कम राशन दिया जाए तो वो इसकी जानकारी तुरंत कार्यालय पर दें। गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहें वह कोई भी हो। उन्होंने पूर्ति विभाग के अफसरों से भी अपील करते हुए कहा कि राशन वितरण जितना पारदर्शी होगा, उतना ही बेहतर होगा। कुंदरकी विधायक के जनसहयोग कार्यालय पर सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने में मदद की जा रही है।

राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि योजना आदि का लाभ उपलब्ध कराया जाता है।

इस अवसर जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर बिलारी शैलेन्द्र सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर सदर संतोष कुमार, बीडीओ राजेंद्र सिंह ,एडीओ अमरीश यादव, चेयरमैन मेहन्दी हसन ,ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गुलाम जिलानी ,रामकिशोर लोधी, मंडल अध्यक्ष संजय कश्यप ,बबलू जाटव, नीरज चंद्रा, महेंद्र सैनी, संजय दिवाकर, बिजेंद्र चौधरी, बिजेश लोधी, अरविंद ठाकुर, अशोक प्रजापति, गौरव, सुनील , टिंकू, रोहित सिंह आदि उपस्थित रहे।

छेड़खानी...वीडियो फिर ब्लैकमेलः मोसीन ने किशोरी का जीना किया दुश्वार, पुलिस पर शिकायत की तो दे रहा यह धमकी

मुरादाबाद ।

सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी से युवक ने डरा धमका कर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। वीडियो के जरिए आरोपी पांच माह तक पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी मोसीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सिविल लाइंस क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली अनुसूचित जाति की महिला ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि चकर की मिलक में रहने वाला मोसीम ने पांच माह पहले उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की। इसके बाद आरोपी ने उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। आरोपी पांच माह से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। 17 नवंबर की शाम आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिवार के लोगों को दी तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कराने की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी के परिजन और उसके मोहल्ले के लोग पीड़िता के घर पहुंच गए। उन्होंने पीड़िता की मां पर दबाव बनाया है कि वह इस मामले में समझौता कर ले लेकिन पीड़िता की मां आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कराने पर अड़ गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी मोसीम के खिलाफ दुष्कर्म, एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।

चौकी में थर्ड डिग्री टॉर्चर : पैसे भी लिए... कारोबारी से मिला था चौकी प्रभारी, एसएसपी ने कर दिया निलंबित

मुरादाबाद । मंडी चौक पुलिस चौकी के इंचार्ज राज किशोर ने पीतल कारोबारी विशेष अरोड़ा की शिकायत पर तीन युवकों को बुलाकर उत्पीड़न किया। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने तीनों पर दबाव बनाया है कि वह कबूल करें कि उन्होंने कारोबारी के शोरूम से पीतल के उत्पाद चोरी किए हैं। उन्होंने चोरी नहीं कबूली तो डंडे और पट्टे से पिटाई की और बाद में रुपये लेकर तीनों को छोड़ दिया। इसकी शिकायत मिलने पर एसएसपी सतपाल अंतिल ने चौकी इंचार्ज राज किशोर को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। सिविल लाइंस थानाक्षेत्र में आकाश ग्रीन अपार्टमेंट में रहने वाले हिमांशु वर्मा, लाइनपार मझोली चौराहा निवासी रोहताश और मूंढापांडे के सेहरिया निवासी अनीस बुधवार को एसएसपी सतपाल अंतिल के सामने पेश हुए। उन्होंने बताया कि तीनों कोतवाली के सागर सराय निवासी पीतल कारोबारी विशेष अरोड़ा के मंडी चौक स्थित शोरूम और फर्म में पहले काम कर चुके हैं। 17 नवंबर को उन्हें मंडी चौक चौकी के इंचार्ज राजकिशोर ने चौकी में बुलाया था। आरोप है कि तीनों को चौकी के अंदर बैठाकर पूछताछ की। उन्हें बताया गया कि विशेष अरोड़ा ने तीनों पर चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने चोरी करने की बात से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि इस बात पर चौकी इंचार्ज भड़क गए। उन्होंने डंडे और पट्टे से तीनों की पिटाई की जिसमें तीनों को चोटें भी आई हैं। तीनों का आरोप है कि उन्होंने चोरी की बात नहीं कबूली तो चौकी इंचार्ज ने उनसे रुपयों की मांग की। हिमांशु का दावा है कि उनसे 23 हजार रुपये भी लिए गए हैं। एसएसपी ने तुरंत ही सीओ सुनीता दहिया, कोतवाली प्रभारी बिजेंद्र सिंह और चौकी इंचार्ज राजकिशोर को अपने कार्यालय में तलब कर लिया। तीनों युवकों का पुलिस से आमना-सामना कराया। सीओ और कोतवाली प्रभारी को इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी। चौकी इंचार्ज ने शिकायती पत्र आने की भी जानकारी अपने अफसरों को नहीं दी थी। एसएसपी सतपाल अंतिल ने सीओ कोतवाली से पूरे प्रकरण की जांच कराई।

जांच में तीनों युवकों द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। एसएसपी ने बृहस्पतिवार को चौकी इंचार्ज राज किशोर को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

दिल्ली में सनसनीखेज हत्या: बहन को परेशान करने वाले का गला पेपर कटर से काटा, मामा-भांजा गिरफ्तार

दिल्ली। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कीर्ति नगर थाना इलाके में रेलवे ट्रैक के पास 32 वर्षीय शख्स की हत्या के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है. साजिशकर्ता समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हत्या के मुख्य आरोपी की तलाश जारी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या बदले की भावना से की गई थी. बताया जा रहा है कि मृतक शख्स मुख्य आरोपी की बहन को लगातार परेशान कर रहा था. डीसीपी दराडे शरद भास्कर ने बताया कि, 17 नवंबर को कीर्ति नगर पुलिस को रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के गले पर गहरा कट पाया गया और उसके सामान भी मौके से गायब थे. मृतक की पहचान बसई दारापुर के रहने वाले अंगद (32 वर्ष) के रूप में हुई थी. इस मामले में कीर्ति नगर थाना में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गयी थी. हत्या की गंभीरता को देखते हुए ACP पंजाबी बाग, शिवम की देखरेख और SHO कीर्ति नगर संजीव धौड़ी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया था. टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी निगरानी की मदद से घटना से जुड़े सुराग जुटाए. सीसीटीवी विश्लेषण में मृतक को आखिरी बार दो युवकों अमर और उसके चचेरे भाई सत्येंद्र के साथ देखा गया. जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय जानकारी और तकनीकी इनपुट के आधार पर सत्येंद्र को दबोच लिया. पूछताछ के दौरान उसने हत्या में अमर के पिता हरीश चंद्र की भूमिका का खुलासा किया, जिसके बाद हरीश को भी गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार, मृतक अंगद, हरीश चंद्र की बेटी और अमर की बहन को लंबे समय से परेशान कर रहा था.

वह उसे आपत्तिजनक संदेश भेजता था, धमकियां देता था और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की बात करता था. परिवार द्वारा कई बार समझाने के बावजूद मृतक का व्यवहार नहीं बदला. इसी कारण हरीश चंद्र ने उसे बेटे अमर और भांजे सत्येंद्र की सहायता से उसे मारने की योजना बनाई. जिसे अंजाम देने की नीयत से अमर 14 नवंबर को दिल्ली आया और सत्येंद्र के साथ ठहरा. 16 नवंबर की शाम दोनों मृतक के कमरे तक पहुंचे, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के कारण वे मृतक अंगद को शराब पीने और मामला सुलझाने के बहाने रेलवे लाइन की तरफ गए, जहां सीसीटीवी कवरेज नहीं था. वहीं अंगद की गला रेतकर हत्या कर दी गई और दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. इस दौरान हरीश चंद्र लगातार उनके सम्पर्क में था. गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पेपर कटर चाकू, मृतक का मोबाइल फोन और आरोपी सत्येंद्र के खून से सने कपड़े बरामद किये हैं. हरीश चंद (56 वर्ष) मेटल फोर्जिंग फैक्ट्री में कार्यरत है जबकि सत्येंद चौधरी (39 वर्ष) पेशे से पेंटर है और दोनों रिश्ते में मामा-भांजा हैं. हत्या का मुख्य आरोपी अमर अभी भी फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.

एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुन कर बाहर निकालेंगे, अमित शाह बोले- एसआईआर लोकतंत्र को बचाने का अभियान

भुज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को गुजरात के भुज में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 61वें स्थापना दिवस (रेजिंग डे) समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनके योगदान की तारीफ की। साथ ही नागरिकों को 12 राज्यों में मतदाता सूची में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों को इसका पूरी तरह समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया देश और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए अहम है। इसके जरिए हर एक घुसपैठिए को मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। शाह ने संबोधन में कहा, मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। एसआईआर की प्रक्रिया देश और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों का नाम लिए बिना कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को निकालने के इस अभियान को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि जनता ने इस मुद्दे पर एनडीए को बहुमत दिया है। शाह ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव आयोग की मतदाता सूची को सही करने के लिए लाई गई एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं आज देशवासियों से अपील करता हूं कि वे खुलकर और पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन करें। मैं घुसपैठियों का बचाव कर रहे राजनीतिक दलों को चेतावनी देना चाहता हूं कि बिहार चुनाव पूरे देश के जनादेश की तरह है।

राहुल गांधी का बड़ा बयान: नेहरू सिर्फ इतिहासकार नहीं, बल्कि भारत की धड़कन हैं, डिजिटल संग्रह का उद्घाटन

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू के लेखन के एक व्यापक डिजिटल संग्रह के उद्घाटन की सराहना की और इसे भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली दिशासूचक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के पहले प्रधानमंत्री के कार्य केवल ऐतिहासिक अभिलेख नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र की विकसित होती अंतरात्मा को दर्शाते हैं, जो उसके साहस, शंकाओं और आकांक्षाओं को समेटे हुए है। संग्रह के महत्व पर अपने विचार साझा करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू के लेखन आधुनिक भारत को आकार देने वाली चुनौतियों और

विचारों के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि नेहरू के लेखन केवल इतिहास नहीं है, वे भारत की विकसित होती अंतरात्मा का अभिलेख है। हमारे राष्ट्र की लोकतांत्रिक यात्रा- उसके साहस, उसके संदेहों, उसके सपनों - को समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए, उनके शब्द एक शक्तिशाली दिशासूचक बने हुए हैं। मुझे खुशी है कि यह विरासत अब सभी के लिए खुली, खोज योग्य और मुफ्त है। इसका विस्तार होता रहेगा। जवाहरलाल नेहरू की चुनिंदा कृतियों का पूर्णतः डिजिटलीकरण कर दिया गया है।

नए लॉन्च किए गए डिजिटल संग्रह में नेहरू के निबंध, पत्र, भाषण और व्यक्तिगत विचार स्वतंत्र रूप से सुलभ और खोज योग्य है, जिससे शोधकर्ता, छात्र और नागरिक भारत के पहले प्रधानमंत्री के विचारों को एक सुविधाजनक प्रारूप में खोज सकते हैं। इस संग्रह को निरंतर विस्तारित करने के लिए डिजाइन किया गया है, और समय के साथ इसमें अतिरिक्त लेखन और दस्तावेज़ों को शामिल करने की योजना है। राहुल गांधी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि नेहरू की बौद्धिक और राजनीतिक विरासत अब बिना किसी प्रतिबंध के जनता के लिए उपलब्ध है। उन्होंने इस पहल को ऐतिहासिक साक्षरता और लोकतांत्रिक जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो नागरिकों को उन मूलभूत विचारों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्होंने भारत को एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में मार्गदर्शन किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कल घोषणा की थी कि जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष ने एक स्मार्टफोन-अनुकूल http://nehruarchive.in लॉन्च किया है।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 15 मजदूरों की मौत, 7 अस्पताल में भर्ती

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को एक फैक्टरी के बॉयलर में विस्फोट होने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। एक अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी। यह घटना लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर पंजाब के फैसलाबाद जिले में सुबह हुई। फैसलाबाद के उपायुक्त राजा जहांगीर अनवर ने संवाददाताओं को बताया कि मलिकपुर इलाके में एक रसायन कारखाने के बॉयलर में शक्तिशाली विस्फोट के कारण एक इमारत सहित आस-पास के ढांचे ढह गए। अनवर ने कहा, ''अब तक बचाव दल ने मलबे से 15 शव बरामद कर लिए हैं और सात घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।

गोधरा में एसी में शॉर्ट सर्किट से पूरे घर में फैली आग, पति-पत्नी और दो बेटों की मौत

नई दिल्ली।

गुजरात के गोधरा शहर में एक घर में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना गोधरा के वृंदावन नगर 2 इलाके की है। जहां आग लगने से निकले धुएं में दम घुटने से एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, 21 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे घर के ग्राउंड फ्लोर पर पड़े सोफे में अचानक आग लग गई। आग का धुआं तेजी से पूरे घर में फैल गया। धुएं के कारण दम घुटने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। ए डिविजन पुलिस स्टेशन ऑफिसर आरएम वसैया ने बताया कि सभी लोग नींद में सो रहे थे। इसी वक्त आग लगी और धुआं पूरे घर में भर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मरने वालों में जौहरी कमल दोशी (50), उनकी पत्नी देवलबेन (45), और उनके बेटे देव (24) और राज (22) शामिल थे।

बड़ा दावा: एनडीए ने 5.5 रुपये रोजाना में खरीदा बिहार का वोट

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत और जन सुराज की करारी हार के बाद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के वोट को आर्थिक सहायता के बहाने खरीदा गया। भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम में गुरुवार को प्रायश्चित उपवास और मौन व्रत रखने के बाद किशोर ने कहा कि यह उनकी हार के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर हुए अन्याय के कारण कठिन समय था। उनका दावा है कि चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में रोजाना साढ़े पांच रुपए प्रति दिन भेजकर जीविका दीदियों के माध्यम से वोट बैंक को नियंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि यह तरीका गरीब लोगों के अधिकारों के साथ अन्याय है, जिन्होंने अपनी उम्मीदों और बच्चों के भविष्य के सपनों के बदले राजनीतिक खेल का शिकार होना पड़ा। किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार खुद ईमानदार नेता है, लेकिन उनके नाम का उपयोग कर भ्रष्टाचार और वोटिंग में मनमानी की गई। वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले कर्ज का पैसा डायवर्ट कर जनता के खाते में भेजा गया, जिससे चुनावी परिणाम पर सीधा असर पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया तो सत्ता में रहने वाली पार्टी कभी चुनाव हारने की स्थिति में नहीं होगी। उन्होंने गांधी आश्रम का उदाहरण देते हुए बताया कि जन सुराज की शुरुआत यहीं से हुई थी। पैदल चलकर शुरू किए गए आंदोलन ने लाखों लोगों को जोड़कर एक बड़ा परिवार बना दिया।

किशोर ने कहा कि बिहार में बदलाव की उम्मीद जगी थी, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद पर हुए इस तरह के खेल ने पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घटना भारतीय चुनाव इतिहास में पहली बार दर्ज हुई है और इसका प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।

महाराष्ट्र सरकार का फरमान! अधिकारियों को एमपी-एमएलए का करना होगा सम्मान, न करने पर होगी सख्त कार्रवाई

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों के लिए नया कोड ऑफ़ कंडक्ट जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे जनप्रतिनिधियों यानी एमपी और एमएलए को कार्यालय में विशेष सम्मान देंगे।

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि के कार्यालय में आने और मीटिंग से लौटने पर अधिकारी खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। यह प्रोटोकॉल मंत्रालय से लेकर जिला और तालुका स्तर तक सभी अधिकारियों पर लागू होगा। सर्कुलर में अधिकारियों के व्यवहार, संचार, मीटिंग नियम, सरकारी कार्यक्रमों और रिस्पॉन्स टाइमलाइन से जुड़े व्यापक दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत में

अधिकारी पूरी तहज़ीब और सम्मान का प्रदर्शन करें। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नए प्रोटोकॉल का पालन न करने, देरी या लापरवाही की स्थिति में महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स और सरकारी काम में देरी रोकने के लिए बने 2005 के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकार ने तय समय निर्धारित किया है। रीजनल और जिला प्रमुखों को हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को एमपी और एमएलए के साथ दो घंटे की विशेष मीटिंग रखनी होगी। यह शेड्यूल पहले से प्रकाशित कर सभी जनप्रतिनिधियों को सूचित करना अनिवार्य होगा। जीआर में कहा गया है कि एमपी या एमएलए द्वारा उठाए गए अर्जेंट मामलों पर ऑफिस टाइम के दौरान किसी भी समय बातचीत की जा सकती है। साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि जब विधानमंडल या संसद सत्र चल रहा हो, तब बड़े सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन न किया जाए। यदि कोई कार्यक्रम जरूरी हो, तो उसे ऐसे दिन तय किया जाए जब हाउस न चल रहा हो। सभी विभागों को विधानमंडल की प्रिविलेज कमिटी के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। लेजिस्लेचर सचिवालय से मिले नोटिस पर तुरंत कार्रवाई करने और कमिटी को अद्यतन जानकारी देते रहने की अनिवार्यता भी तय की गई है। किसी भी प्रिविलेज ब्रीच को तुरंत रिपोर्ट कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी होगी।

कर्नाटक में सीएम पद का घमासान जारी, डीके शिवकुमार का बड़ा बयान - 140 विधायक मंत्री बनने के योग्य

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार से जूझ रही कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। हालांकि, राज्य में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान आया है। डीके शिवकुमार ने कहा कि समूह बनाना मेरे खून में नहीं है। सभी 140 विधायक मेरे विधायक हैं। सीएम ने फैसला किया है कि वह सरकार और कैबिनेट में फेरबदल करेंगे। इसलिए, वे सभी मंत्री बनने के हकदार हैं।

यह स्वाभाविक है कि वे दिल्ली जाकर नेताओं से मिलेंगे। इसके अलावा, मैं क्या कह सकता हूं? उन्हें पूरा अधिकार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं किसी को नहीं ले गया। उनमें से कुछ लोग खड़गे साहब से मिले। उन्होंने सीएम से भी मुलाकात की। क्या गलत है? यह उनकी जिंदगी है। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं है, वे स्वेच्छा से जा रहे हैं और अपना चेहरा दिखा रहे हैं। वे अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते थे कि वे सबसे आगे हैं, काम कर सकते हैं और वे जिम्मेदारी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी 140 विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। वे सब कुछ बन सकते हैं...मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे 5 साल पूरे करेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ। हम सब उनके साथ मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस विधायक टीडी राजेगौड़ा ने कहा कि यह निर्णय हाईकमान और सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को लेना है... मैंने शिवमोग्गा, कुछ सड़क मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि सिद्धारमैया ने शुक्रवार सुबह खड़गे से कांग्रेस पार्टी की छवि और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की लगातार चर्चा से सरकार को हो रहे नुकसान के बारे में बात की। खड़गे ने सिद्धारमैया को आश्वासन दिया कि वह स्थिति का आकलन करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे।

भाजपा कारोबारियों को डरा रही, ताकि वो कुछ कह न सकें; अब इनकी नजर दालमंडी पर है- अखिलेश यादव

लखनऊ। अखिलेश यादव ने लखनऊ में भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लोग खुलकर कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। इनकी नीति है कि लोगों को इतना डरा दो कि वो अपनी बात न कह सकें। क्या ये कोई सरकार करती है। अरे, सबको अपनी बात कहने का हक है। सरकार की नजर अब दालमंडी पर है। एक दुकान बनाने में जमाने लग जाते है ये लोग पल भर में इसे तोड़ना चाहते हैं। भाजपा की बहुत संकीर्ण सोच है। ये साजिश कर रही है। ये चौड़ीकरण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी सोच बहुत नकारात्मक है। किसी की जीविका छीनने का इनको अधिकारी कैसे मिल गया। ये लोग अधिकारियों के जरिए दबाव बनाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, दौलो के सांसद और दाल मंडी के व्यापारी आए हैं। सरकार के फैसले की वजह से व्यापारियों पर संकट आया है। ये पॉलिटिकल डिमोलिशन है। क्योंकि वो वहां से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। बीजेपी ने वाराणसी को क्योटो बनाने का दावा किया था। लोगों को परेशान कैसे किया जाए। इस पर काम हो रहा है। पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए

डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रही है। सरकार को ऐसे शहरों का दौरा करना चाहिए। दाल मंडी वाले दुकानदारों को दरें नहीं। दुकान तो दे देंगे, ग्राहक कहां से देंगे। बीजेपी की सोच संकीर्ण है, वो चौड़ीकरण कैसे कर रहे हैं। ये नकारात्मक सोच वाले हैं। बीजेपी अधिकारियों के माध्यम से डराना, धमकाना चाहते हैं। मॉल बेच दिया। ये बेचने वाले लोग हैं। वरुणा का रिवरफ्रंट रोक दिया। आज मेट्रो जितनी चल रही है, वो सपा की देन है। वाराणसी की मेट्रो का डीपीआर हमने तैयार किया था। वाराणसी के मेट्रो को बीजेपी ने रोका है। अकबरनगर लखनऊ में डिमोलिशन कर दिया। अपनी जगह के लिए मनचाहा मुआवजा लिया। कई साल आगे या कई हजार साल पीछे की बात करते है।

मुख्यमंत्री योगी ने माना, विश्व में साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिटी मांटेसरी स्कूल की कानपुर रोड की शाखा में 26वें इंटरनेशनल चीफ जस्टिस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का समापन आज शाम को रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह करेंगे। इस सम्मेलन में 52 देशों के मुख्य न्यायाधीश भाग ले रहे हैं। सिटी मांटेसरी स्कूल में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है।

हमको भरोसा है कि विश्व एकता और बंधुत्व को लेकर आयोजित यह सम्मेलन विश्व को एक करने में सफल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि दुनिया को अब एक अधिक न्यायपूर्ण,

समावेशी और जवाबदेह वैश्विक प्रणाली की आवश्यकता है। 80 वर्ष पहले की गई इस घोषणा की सार्थकता आज भी उसी रूप में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि न्याय न केवल समता का, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए युग में हम सहज और सरल जीवन जी रहे हैं वहीं दूसरी और चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए हम सबको एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विश्व एकता और शांति के लिए सिटी मांटेसरी स्कूल पिछले 25 वर्ष से जो प्रयास किया जा रहा है वह सराहनीय है। विश्व एकता और बंधुत्व के बहाने हम देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आएगा उसे हम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम् यानी पूरी दुनिया एक परिवार है यह हजारों वर्ष से भारत की मूल सोच रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सम्मेलन भारतीय संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को फिर से पूरी दुनिया में मूर्त रूप से प्रस्तुत करने में सफल होगा। उन्होंने विश्व भर से पधारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गण, न्यायविद् व सभी सम्मानित अतिथि गण का हार्दिक अभिनंदन करने के साथ कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न देशों की कार्यक्रमों की प्रस्तुति को भी देखा।

ईवीएम पर अब दिखेगी उम्मीदवारों की तस्वीर

नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसकके लिए जल्द अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, ईवीएम को लेकर नए नियम जारी किया गया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राज्य में 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जांच और मतदान अभ्यास शुरू करने का कार्यक्रम तय किया है। उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में कई प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) टीम के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने जारी एसआईआर, ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक,

***चुनाव आयोग ने 2026 बंगाल चुनाव की कमान संभाली**

राज्य चुनाव आयुक्त के पास सभी मशीनों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह भी नए नियम लागू किया है कि इस बार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार की छवि सहित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कौन-सी जानकारी दिखाई जाएगी, यह तय किया गया है। यह

पहली बार है जब मशीनों पर उम्मीदवार की तस्वीर भी दिखाई जाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, उम्मीदवार की छवि ईवीएम के बटन के पास रखी जाएगी और प्रशिक्षण के दौरान भी दिखाई जाएगी। आयोग के मुताबिक, 2026 विधानसभा चुनाव में राज्य में लगभग 15 हजार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ जाएगी। 2021 के चुनावों में राज्य में 80,681 मतदान केंद्र थे; 2026 में यह संख्या लगभग 95 हजार होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के पास प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पर्याप्त मशीनें हैं। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय में वर्तमान में 1.30 लाख ईवीएम (बैलट और कंट्रोल यूनिट सहित) और 1.35 लाख वीवीपैट मशीनें मौजूद हैं। आज बाद में चुनाव आयोग के सदस्य एक ईवीएम अभ्यास आयोजित करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मशीनें सही ढंग से काम कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, ईवीएम में कुल छह मतदान बटन होंगे और प्रत्येक बटन का परीक्षण 16 बार किया जाएगा, कुल 96 बार। अधिकारी बंगलूरू की ईवीएम निर्माण कंपनी, ईसीआईएल के इंजीनियर्स से कोलकाता के न्यूटाउन में इको पार्क के बगल में स्थित बैंक्वेट हॉल में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने और जांचने के लिए किया जा रहा है कि सभी बटन सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं; बैलट यूनिट-कंट्रोल यूनिट सही तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे है या नहीं; वीवीपैट में कागज और छवि सही तरीके से आ रही है या नहीं। प्रत्येक जिले में ईवीएम अधिकारी, गोदाम अधिकारी और जिला अधिकारी/जिला चुनाव अधिकारी मौजूद रहेंगे और अपने-अपने जिलों में प्रक्रिया का प्रशिक्षण देंगे।